



परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों के लिये RBI दशा-नरिदेश

प्रलिस के लिये:

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI), परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियाँ, सडिबी, नाबारड, गैर-नषिपादति परसिंपत्तियाँ (NPA), सरफेसी अधनियिम (2002)

मेन्स के लिये:

परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों, बैंकिंग क्षेत्र तथा गैर-नषिपादति परसिंपत्तियों का महत्त्व ।

[स्रोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड](#)

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने 24 अप्रैल, 2024 से प्रभावी परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों (ARCs) के लिये अद्यतन दशानरिदेशों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक नरिदेश जारी किया है ।

परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों (ARC) के लिये RBI दशा-नरिदेश क्या हैं ?

- न्यूनतम पूंजी आवश्यकता में वृद्धि:
 - ARCs को पहले 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती थी; इस आवश्यकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है ।
 - मौजूदा ARCs को 31 मार्च, 2026 तक 300 करोड़ रुपए की नई न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली नधि (NOF) सीमा तक पहुँचने के लिये एक संक्रमण अवधि दी गई है ।
 - उच्च पूंजी आवश्यकता की दशा में परिवर्तन के हिससे के रूप में ARC को 31 मार्च, 2024 तक न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की पूंजी सुनिश्चित करनी होगी ।
 - यदि उपरोक्त किसी भी चरण को पूरा नहीं किया जाता है, तो गैर-अनुपालन करने वाले ARCs को पर्यवेक्षी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें नए व्यवसाय को लेने पर प्रतिबंध शामिल हो सकता है जब तक कि वह उस बट्टि पर प्रभावी न्यूनतम NOF को पूरा नहीं कर लेता ।
- बॉण्ड समाधान आवेदक के रूप में पात्रता:
 - न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए के NOF वाले ARC को [दवाला और दवालियापन संहिता, 2016 \(IBC\)](#) के अंतर्गत परसिंपत्त समाधान प्रक्रिया में समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति है ।
- नविश के अवसर:
 - ARC से प्राप्त धनराशिको सरकारी प्रतिभूतियों में नविश किया जा सकता है तथा साथ ही अनुसूचित वाणजियिक बैंकों [राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक \(नाबारड\)](#), [भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक \(सडिबी\)](#) अथवा अन्य संगठनों के पास जमा किया जा सकता है जिन्हें देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर नरिधारति किया जाता है ।
 - इसके अतिरिक्त, ARC किसी पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा AA- या उससे ऊपर की अल्पकालिक रेटिंग वाले मनी मार्केट [मयुचुअल फंड](#), [जमा प्रमाणपत्र](#) और कॉर्पोरेट बॉण्ड/[वाणजियिक पत्रों](#) जैसे [अल्पकालिक उपकरणों \(Short-term Instrument\)](#) में नविश कर सकते हैं ।
 - हालाँकि, ऐसे अल्पकालिक उपकरणों में अधिकतम नविश पर NOF सीमा 10% होती है ।

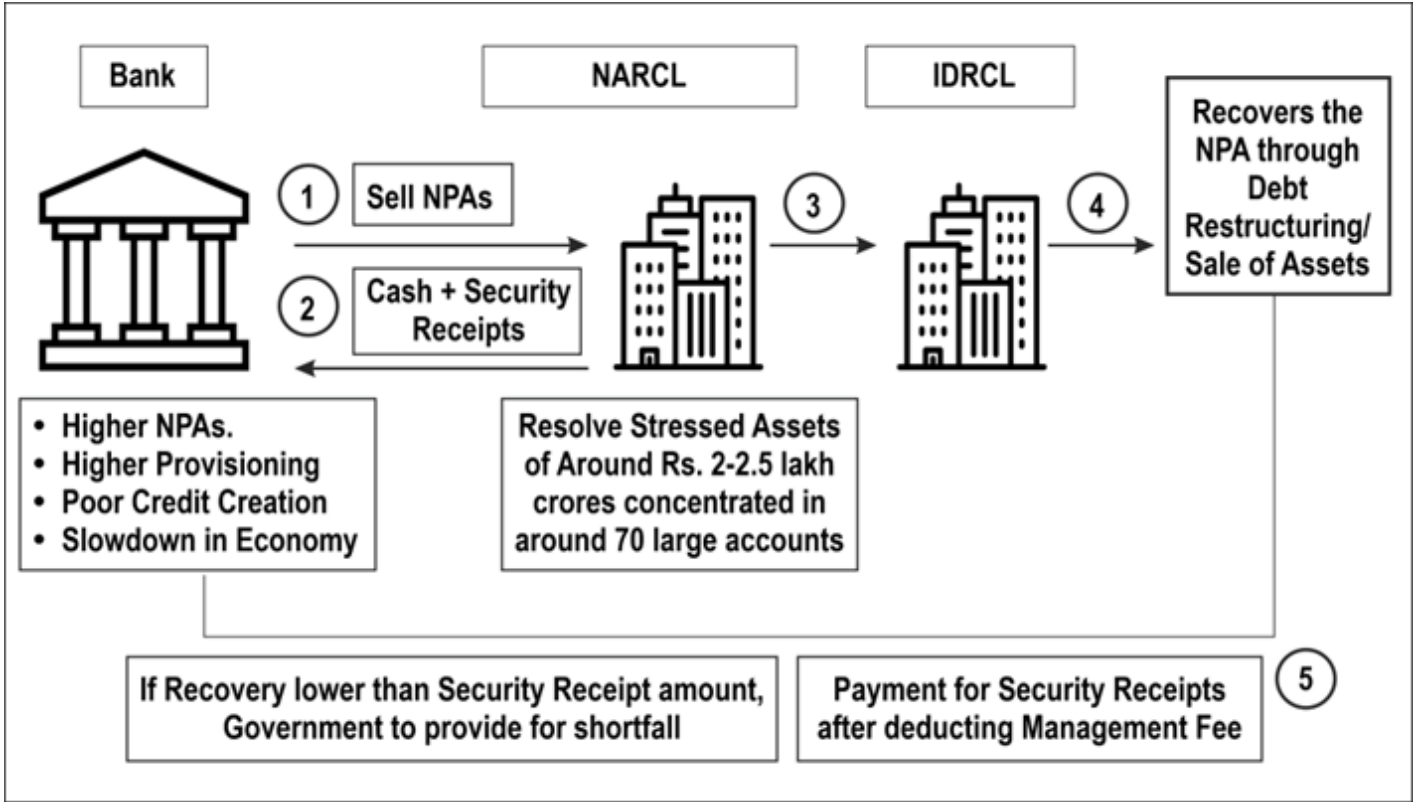
परसिंपत्त पुनर्रिमाण कंपनी (Asset Reconstruction Company- ARC) क्या है?

- परिचय:
 - ARC वृत्तीय संस्थान होते हैं, जो बैंकों और वृत्तीय संस्थानों से [गैर-नषिपादति संपत्ति \(NPA\)](#) या गैर-नषिपादति संपत्ति (Bad Asset) खरीदते हैं ।

- इससे बैंकों और संस्थानों को अपनी बैलेंस शीट साफ करने की सुविधा मिलती है।
- इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है, **वित्तीय संपत्तियों का परतभूतिकरण और पुनर्रमाण एवं सुरक्षा हति का परवरतन (SARFAESI) अधिनियम, 2002** के तहत भारतीय रज़िर्व बैंक के साथ पंजीकृत किया गया है।

▪ उदाहरण:

- **नेशनल एसेट रकिंसटरकशन कंपनी लमिटेड (NARCL)** की स्थापना बैंकों द्वारा बाद के समाधान के लिये लचीली संपत्तियों (Stressed Asset) को एकत्र करने और समेकित करने के लिये की गई है। इसमें 51% हस्सिसेदारी के साथ **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB)** का बहुमत है।
- **इंडिया डेट रेज़ोलयूशन कंपनी लमिटेड (IDRCL)** एक अन्य इकाई है, जो लचीली संपत्तियों को बाज़ार में बेचने का प्रयास करेगी।
 - PSB और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (FI) IDRCL में अधिकतम 49% की हस्सिसेदारी रखेंगे। जबकि शेष 51% हस्सिसेदारी नज़ी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगी।



▪ कार्य:

- **SARFAESI अधिनियम, 2002** द्वारा अधिकार प्राप्त ARC संकटग्रस्त परसंपत्तियों की वसूली और परिवर्तन में वशिषज्जता रखते हैं।

- वे ऋणदाताओं से नकद या नकदी और परतभूति प्राप्तियों के संयोजन के माध्यम से खराब ऋण (Bad Debt) लेते हैं।

▪ व्यापार मॉडल:

- **लचीले ऋणों का अधग्रहण:** ऋणदाता ARC को लचीले ऋणों को छूट पर बेचते हैं, जसिसे नए ऋणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये उनके संसाधन मुक्त हो जाते हैं।
- **परतभूति की प्राप्ति (Security Receipt):** ARC ऋणदाताओं को परतभूति प्राप्ति जारी करती है, जनिहें वशिषिट ऋण की वसूली पर भुनाया जा सकता है।
 - वे वार्षिक परसंपत्त मूल्य का 1.5% से 2% का प्रबंधन शुल्क भी लेते हैं और बकिरी वित्तीय संस्थानों (Selling Financial Institution) के साथ साझा करते हुए वसूली से कमाई करते हैं।

▪ चुनौतियाँ:

- ARC अकसर पुराने NPA से नपिटते हैं, जो लंबे समय तक चूक के कारण मूल्यांकन और वसूली के मामले में चुनौतियाँ पेश करते हैं।
- कई उधारदाताओं से एक ही उधारकर्त्ता पर ऋण एकत्र करना जटिल हो सकता है, जसिके लिये वभिन्न हतिधारकों के बीच समन्वय और समझौते की आवश्यकता होती है।
- ARC को अपनी बैलेंस शीट पर धन जुटाने, संकटग्रस्त संपत्तियों को हासल करने की क्षमता सीमति करने या पुनरुद्धार के लिये उधारकर्त्ताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करने में कठनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- अधग्रहण और पुनरप्राप्ति उद्देश्यों के लिये संकटग्रस्त परसंपत्तियों का खासकर जब अशक्षिषि या जटिल परसंपत्तियों से नपिटना हो, उचित मूल्य नरिधारति करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

▪ RBI द्वारा ARC वनियमों में हालिया परिवर्तन:

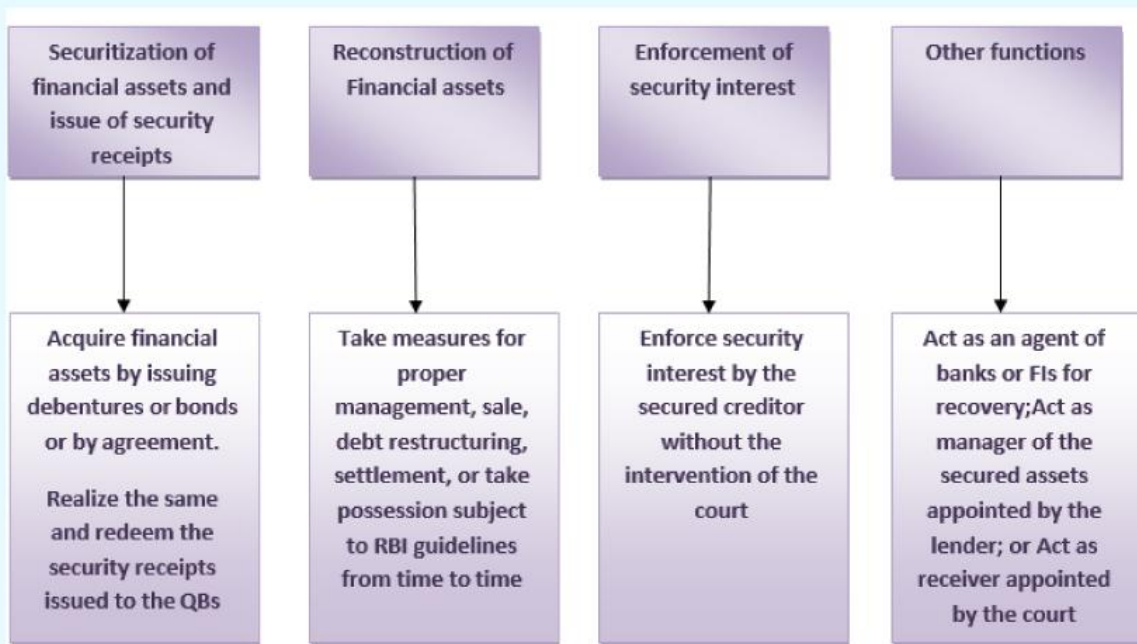
- **कॉर्पोरेट प्रशासन को मज़बूत करना:** ARC में कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाने के लिये RBI ने आदेश दिया कि बोर्ड के अध्यक्ष और

बोर्ड बैठक में कम-से-कम आधे नदिशक स्वतंत्र नदिशक होने चाहिये ।

- **बढ़ी हुई पारदर्शिता:** ARC को सुरक्षा रसीद नविशकों के लिये उत्पन्न रटिर्न पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड का खुलासा करना और पारदर्शिता में सुधार के लिये पछिले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं के लिये रेटिंग एजेंसियों के साथ जुड़ना आवश्यक है ।
- **नविश आवश्यकताएँ:** ARC को **प्रतभूत प्रापतियों (SR)** में ऐसी प्रापतियों में हस्तांतरणकर्त्ताओं के नविश का कम-से-कम 15% या जारी की गई कुल प्रापतियों का 2.5%, सभी मामलों में कुल प्रतभूत प्रापतियों के 15% की पछिली आवश्यकता के वपिरीत, जो भी अधिक हो ।
 - SR ARC द्वारा योग्य खरीदारों (QB) को बैंकों और **गैर-बैंकगि वत्तीय कंपनियों (NBFC)** से संकटग्रस्त संपत्तियों की खरीद के बदले में जारी किये गए उपकरण हैं ।

सरफेसी अधनियिम, 2002

Role of SARFAESI Act, 2002



???????? ???? ????:

प्रश्न. भारतीय वत्तीय परदृश्य में परसंपत्त पुनर्रिमाण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies) के सामने आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रयानवति करने के उपाय सुझाइए ।

??????????:

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. पछिले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतरवेशन में लगातार वृद्धि हुई है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थिति करने के लिये मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का वलिय किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सरकार ने क्रेडिट वसितार का समर्थन करने और गैर-निष्पादित परसिंपत्तियों (NPA) के लिये किये जाने वाले प्रावधानों से होने वाले नुकसान से निपटने में मदद हेतु राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में पूंजी अंतरवेशन का कार्य किया है।
- परंतु सरकारी बैंकों में पूंजी अंतरवेशन का चलन किसी एक दिशा में वशिष्ट नहीं रहा है, यह बढ़ता-घटता रहा है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- फरवरी 2017 में केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भारतीय महिला बैंक और पाँच सहयोगी बैंकों के वलिय को मंजूरी दी थी। वलिय का उद्देश्य सार्वजनिक बैंक संसाधनों का युक्तिकरण, लागत में कमी, बेहतर लाभप्रदता और जनता के लिये ब्याज की बेहतर दर के लिये धन की कम लागत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उत्पादकता एवं ग्राहक सेवा में सुधार करना था। संसद ने सार्वजनिक बैंक के युक्तिकरण को प्रभावित करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक के साथ छह सहायक बैंकों का वलिय करने हेतु स्टेट बैंक (नरिसन और संशोधन) अधिनियम, 2017 पारित किया। **अतः कथन 2 सही है।**

प्रश्न. भारत में गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (NBFC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2010)

1. वे सरकार द्वारा जारी प्रतभूतियों के अधिग्रहण में शामिल नहीं हो सकतीं।
2. वे बचत खाते की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकतीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और ना ही 2

उत्तर: (b)